(a) the estimated buffer stock of foodgrains with the Food Corporation of India as on 1st April, 1988;

(b) whether the buffer stock of foodgrains have come down in comparison to the preceding three years; and

(c) the details of steps being taken by Government to maintain the buffer stock?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) As on 1st April, 1988, total stock of foodgrains with public agencies including Food Corporation of India was estimated at 9.43 million tonnes.

(b) Yes, Sir.

(c) There is regular replenishment of stocks through procurement operation in the country. The Government has also contracted for import of 2 million tonnes of wheat and 7 lakh tonnes of rice.

बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3108. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1984–85 के प्रारम्भिक वर्ष तक इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में गड़बड़ी किये जाने के अनेक आरोप लगाये गये हैं जिनकी पुष्टि हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ; और

(घ) भविष्य में इस कार्यक्रम के प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन किए जाने के लिये सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.) जिसे अक्तूबर, 1980 से पहले चल रहे काम के बदले अनाज कार्यक्रम के स्थान पर शुरू किया गया था, बिहार में इसके आरम्भ होने लेकर अब तक चल रहा है।

(ख) और (ग) विगत में कुछ अन्य राज्यों की भांति बिहार में निधियों के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थीं। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने 1981-82 से 84–85 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में हाल ही में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ एक कमियों का उल्लेख किया है। उनके द्वारा बताई गई कमियों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिये)**

(घ) सातवीं योजना में योजना अवधि के दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए बेहतर आयोजना, कड़ी निगरानी और मजबूत संगठन पर बल दिया गया है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी, मासिक, तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मात्रा तथा क्वालिटी संबंधी पहलुओं पर शीघ्र जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से 30 प्रतिष्ठित संस्थाओं की मार्फत सतत आधार पर सभी जिलों को कवर करने हेतु समवर्ती मूल्यांकन की एक योजना शुरू की गई है। सूचना पद्धति में सुधार करने और फील्ड से शीघ्र जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर कंप्यूटर प्रणाली भी आरम्भ की गयी है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 1981–82

मे 1984-85 की अपनी रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दर्शाने वाला विवरण

1. जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी.) के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु निर्धारित मानदण्ड को नहीं अपनाया गया था।

2. निधियों का उपयोग 1981-82 मे 1984-85 के दौरान 52 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच था। 1984-85 के अन्त में 1,232.62 लाख रुपये उपयोग न किये गये बचे थे।

3. 265.29 लाख रुपये ऐसे कार्यों और प्रयोजन के लिए खर्च किए गए थे जो एन.आर.ई.पी. के कार्य क्षेत्र मे बाहर के थे।

4. जिलों में शैल्फ आफ प्रोजेक्ट और वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई थी।

5. 1981-82 से 1984-85 के दौरान लिए गये 37,904 कार्यों में से 14,924 कार्य अधूरे रह गये थे। 262 अधूरे कार्यों, जिन पर 38.75 लाख रुपये खर्च किए गए थे, को बन्द कर दिया गया था और उन्हें पूरा मान लिया गया था। कार्यों का श्रेणीवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

6. हालांकि राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का निष्पादन पहली अप्रैल, 1981 से शुरु हुआ था, 1980-81 के दौरान 342.96 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजन दर्शाया गया था। 1981-85 के दौरान 1652.07 लाख श्रम दिनों की सूचित उपलब्धि मस्टर रोल के अनुसार वास्तविक श्रमिकों पर आधारित नही थी बल्कि उसका हिसाब किए गये काम की मात्रा को श्रमिक द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले अनुमानित कार्य की मानक दर से विभाजित करके काल्पनिक तौर पर लगाया गया था।

7. 145.39 लाख रुपये की लागत के कार्य ठेकेदारों की मार्फत करवाये गये थे। ठेकेदारों की भागीदारी पर पाबंदी का अनुपालन न करने से ग्रामीण गरीबों को बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसरों से वंचित रहना पड़ा।

8. श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में 2 से 31 सप्ताह तक की देरी हुई।

9. धनबाद जिले के चास ब्लाक में (मार्च-अप्रैल, 1983 के दौरान 6 रुपये प्रतिदिन के मुकाबले 11.83 रुपये) और गिरडीह में (नवम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 के दौरान 5 रुपये प्रतिदिन के मुकाबले 8.60 रुपये से 7 रुपये) अधिक मजदूरी का भुगतान किया गया जिसके कारण अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन नहीं हो सका।

10. मजदूरी भुगतान के एक भाग के रुप में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 1 किलोग्राम के स्थान पर खाद्यान्नों का औसत उपयोग 1982-83 और 1983-84 में क्रमशः 0.330 कि० ग्रा० और 0.319 कि० ग्रा० था।

11. 1983-84 और 1984-85 के दौरान सृजित की गई 10,513.36 लाख रुपये की टिकाऊ तथा गैर-टिकाऊ परिसम्पत्तियों के ब्यौरे उपलब्ध नही थे। कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित की गई परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी।